

ब्यूज टुडे

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य नियमों का मसौदा जारी किया

CCTS योजना के तहत ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 का मसौदा जारी किया गया है।

मुख्य मसौदा नियमों पर एक नज़र

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) को उत्पादन या उत्पादन की प्रति इकाई के संबंध में प्रति टन उत्सर्जित CO₂ के बराबर के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- इसके तहत 400 से अधिक औद्योगिक संस्थाओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी GHG उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) उत्सर्जन लक्ष्यों को निर्धारित करेगा।
- ये नियम एल्यूमीनियम, लोहा व इस्पात, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर लागू होंगे।
- इसका पालन न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वित्तीय दंड लगाया जाएगा।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के बारे में

- लक्ष्य: कार्बन मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देकर GHG उत्सर्जन को कम करना, अर्थात GHG उत्सर्जन पर निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा।
- कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम (ECA), 2022 के तहत केंद्र सरकार को BEE के साथ परामर्श कर CCTS लागू करने का अधिकार है।
- इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
 - अनुपालन तंत्र (बाध्यकारी संस्थाओं के लिए): इसके तहत बाध्यकारी संस्थाओं को अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने पर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है।
 - स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र: यह अन्य क्षेत्रों को GHG उत्सर्जन में कटौती करने, उन्हें समाप्त करने और उन्हें रोकने के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कराने में सक्षम बनाता है। इसके बदले उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है।
- प्रशासक: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)
- कार्बन ट्रेडिंग का विनियामक: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)
- महत्व: यह योजना भारतीय कार्बन बाजार (इन्फोग्राफिक देखें) की नींव रखती है। साथ ही, यह UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप भी है।

विश्व बैंक की “स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025” रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु वित्त एवं कार्बन मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को सराहा गया है।



कार्बन बाजार के संबंध में भारत का अनुभव
उत्सर्जन में कटौती के लिए बाजार आधारित चार प्रमुख तंत्र

- परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना**
उद्देश्य: ऊर्जा-गहन उद्योगों में निर्धारित ऊर्जा खपत (SEC) को कम करना।
मुख्य विशेषताएं:
- ऊर्जा दक्षता में सुधार करने पर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट (ESCerts) जारी किए जाते हैं।
 - टाइगेट क्षेत्रक: इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम और बिजली जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रक।

- नवीकरणीय ऊर्जा सर्टिफिकेट (REC) योजना**
उद्देश्य: नवीकरणीय ऊर्जा खरीद संबंधी दायित्वों (RPO) को पूरा करने में मदद करना।
मुख्य विशेषताएं:
- यह योजना राज्यों को अपने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद संबंधी दायित्वों को पूरा करने में मदद करती है।
 - यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय लाभों के साथ-साथ उसके स्वतंत्र रूप से व्यापार को भी संभव बनाती है।

- रेट-बेस्ड एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ETS)**
उद्देश्य: भारत को CCTS के जरिए प्रदर्शन आधारित (Performance-based) उत्सर्जन व्यापार की ओर बढ़ाना।
मुख्य विशेषताएं:
- कुल उत्सर्जन पर कोई सीमा नहीं (जैसे एक्सोस्यूट कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली में होती है)।
 - हर इकाई को उत्सर्जन तीव्रता के रूप में प्रदर्शन मानक दिया जाता है।
 - कुल उत्सर्जन को घटाने की बजाय उत्सर्जन तीव्रता सुधारने पर जोर दिया जाता है।

- क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (CDM)**
क्योटो प्रोटोकॉल (1997 में अपनाया गया) का भाग - अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट तंत्र
मुख्य विशेषताएं:
- विकासित देश, विकासशील देशों में GHG उत्सर्जन में कमी वाली परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
 - इसके बदले विकासित देशों को सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन (CER) क्रेडिट्स मिलता है, जिनका व्यापार किया जा सकता है।
 - इससे संश्लेषणीय विकास को बढ़ावा मिलता है और साथ ही, जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद मिलती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'संधारणीय विकास के लिए निजी पूंजी जुटाने हेतु सात सूत्री रणनीति' का प्रस्ताव रखा

हाल ही में, वित्त मंत्री ने स्पेन के सेविले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित “विकास के लिए वित्त-पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4)” को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने सात सूत्री रणनीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

निजी पूंजी जुटाने के लिए सात सूत्री रणनीति के बारे में

- मजबूत घरेलू वित्तीय बाजार: अवसरचना और उद्योग को वित्त-पोषित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली एवं पूंजी बाजार को मजबूत करना।
- संस्थागत सुधारों के जरिए संभावित जोखिम का समाधान: इसमें स्वतंत्र विनियामकों की स्थापना करना, पारदर्शी बोली प्रक्रिया को लागू करना तथा व्यापार करने की सुगमता को और बेहतर बनाना शामिल है।
- निवेश हेतु अवसरों को बढ़ाना: सुनियोजित रूप से तैयार, जोखिम रहित और निवेश के लिए उपयुक्त परियोजनाओं की योजना बनाना।
- मिश्रित वित्त को बढ़ावा देना: निजी निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिए सार्वजनिक और रियायती वित्त का लाभ उठाना तथा सॉवरन ग्रीन बॉण्ड, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे नवीन साधनों का उपयोग करना।
- बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) और विकास वित्त संस्थाओं (DFIs) की भूमिका को सक्रिय बनाना।
- उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की दीर्घकालिक क्षमता एवं स्थिरता को सटीक रूप से दर्शाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग पद्धतियों का विकास करना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्थन देने हेतु जमीनी स्तर पर पूंजी उपलब्ध कराना।

संधारणीय विकास में निजी पूंजी का महत्व

- प्रेरक बल: निजी पूंजी उत्पादकता बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहन देने, और मांग को बढ़ाने में मदद करती है।
- वित्तीय उपलब्धता बढ़ाना: संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में हर साल लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर निवेश की कमी बनी हुई है, जिसे निजी पूंजी से पूरा किया जा सकता है।
- समावेशन में सुधार करना: महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs और ग्रामीण समुदायों सहित वंचित समूहों के लिए वित्त की उपलब्धता बढ़ती है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (पूर्ववर्ती UNCTAD) ने 'वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2025' जारी की

इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हालिया वर्षों में घटित विभिन्न संकटों के कारण वैश्विक सार्वजनिक ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है और इसका अत्यधिक बोझ विकासशील देशों पर पड़ा है।

वैश्विक सार्वजनिक ऋण

- उच्च सार्वजनिक ऋण: वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 में 102 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
 - यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो दशक के अंत तक यह ऋण बढ़कर GDP के 100% तक हो सकता है।
- ऋण में असमान रूप से वृद्धि: यद्यपि इसमें विकासशील देशों की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम (लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर) रही है। फिर भी 2010 के बाद से यह विकासशील देशों के मामले में विकसित देशों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ा है।
 - विकासशील देशों के मामले में एशिया और ओशिनिया की वैश्विक सार्वजनिक ऋण में 24% की हिस्सेदारी है। इसके बाद लैटिन अमेरिका व कैरेबियन (5%) और अफ्रीका (2%) का स्थान है।
- ऋण की उच्च लागत: विकासशील देशों को ऋण की उच्च लागत का सामना करना पड़ता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वहन की जाने वाली लागत की तुलना में दो से चार गुना तक अधिक है।
 - 61 विकासशील देशों ने अपने सरकारी राजस्व का 10% या उससे अधिक हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए निर्धारित किया है।
- प्रभाव: इसमें विकास संबंधी वित्त-पोषण में कमी आना, सहायता हेतु वित्त प्रवाह में कमी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम व्यय होना आदि शामिल हैं।

सार्वजनिक ऋण (Public Debt) का महत्त्व



विकासात्मक उद्देश्यों हेतु व्यय का वित्त-पोषण



बाह्य ऋण घरेलू बचत में मदद करता है और विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता है।



आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने और आर्थिक गिरावट का प्रबंधन करने में सहायक।

ऋण प्रबंधन और संधारणीय वित्त-पोषण के लिए सिफारिशें

सार्वजनिक ऋण पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेषज्ञ समूह ने निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है:

- बहुपक्षीय सुधार: संकट के समय ऋण चुकाने में कुछ समय की राहत को सामान्य प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए; G-20 साझा फ्रेमवर्क में सुधार करना चाहिए; IMF के रिजिलियेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के माध्यम से SDR का बेहतर उपयोग करना चाहिए आदि।
- देशों के बीच सहयोग: नवीन वित्तीय साधनों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक साझा सूचना केंद्र की स्थापना करनी चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर के उपाय: इसमें तरलता संबंधी जोखिम व करेंसी मिसमैच को दूर करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, निवेश परियोजनाओं की योजना बनाना, चयन और तैयारी की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, डेब्ट स्वेप का बेहतर रूप से उपयोग करना आदि शामिल हैं।

RBI ने अपनी अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया

यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति द्वारा तैयार की जाती है। इसमें भारत की वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा इसके समक्ष मौजूद जोखिमों का सामूहिक आकलन प्रस्तुत किया जाता है।

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।
 - FSDC के सदस्यों में भारतीय रिजर्व (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जैसी सभी मुख्य वित्तीय विनियामक संस्थाओं के प्रमुख शामिल होते हैं।
- इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और अलग-अलग विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है।
- RBI रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
 - भारत अभी भी वैश्विक संवृद्धि का संचालक:
 - भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती: 2025-26 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6.5% की वृद्धि का अनुमान है। मजबूत घरेलू मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकटों से निपटने में मदद मिल रही है।
 - मजबूत वित्तीय संस्थान: उदाहरण के लिए- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात और निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA) अनुपात क्रमशः 2.3% व 0.5% है। ये अनुपात पिछले कई दशकों में सबसे कम हैं।
 - 2025 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 'जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)' 17.3% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
 - कॉर्पोरेट क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन: कॉर्पोरेट क्षेत्र के बड़े कर्जदाता समूह का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात सितंबर, 2023 के 3.8% से घटकर मार्च, 2025 में 1.9% हो गया।
 - मुद्रास्फीति की स्थिति:
 - घरेलू मुद्रास्फीति: मई, 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति कम होकर 2.8% हो गई, जो पिछले 6 वर्षों का न्यूनतम स्तर है।
 - आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation): धीमी वैश्विक आर्थिक संवृद्धि की वजह से कच्चा माल और तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। हालांकि, मध्य पूर्व में तनाव की वजह से इनकी कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है।
 - वैश्विक मैक्रोफाइनेंशियल जोखिम:
 - देशों के बीच वैश्विक व्यापार में तनाव, जारी भू-राजनीतिक संघर्ष, बढ़ते वैश्विक सार्वजनिक ऋण और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संभावित मंदी जैसे कारक उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार और आर्थिक नीतियों में अनिश्चितता के कारण वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसके साथ ही, वित्तीय परिस्थितियां भी पहले की तुलना में अधिक कठोर होती जा रही हैं।
 - जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परिघटनाओं की वजह से अवसरनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। इससे व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

वित्तीय क्षेत्र के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण विनियामक पहलें

वैश्विक पहलें:

- बैंकिंग क्षेत्र में: बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा बैंकों के लिए बेसल III मानदंडों के प्रभाव का आकलन किया जाता है।
- वित्तीय बाजार: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) वैश्विक बाजार नियमों को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करता है।
- साइबर सुरक्षा: वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) ने FIRE फ्रेमवर्क जारी किया है। यह फ्रेमवर्क व्यवसाय संचालन में और साइबर घटनाओं से निपटने में मदद करता है। इसमें थर्ड पार्टी सेवा-प्रदाताओं से जुड़ी घटनाओं को भी कवर किया जाता है।

भारतीय पहलें:

- अन्य देशों के साथ व्यापार के भुगतान में रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- संशोधित चल निधि कवरेज अनुपात (Liquidity Coverage Ratio: LCR) नियमावली जारी की गई है।
- डिजिटल लेंडिंग पर RBI ने नए दिशा-निर्देश, 2025 जारी किए हैं।

डिजिटल इंडिया मिशन ने 10 साल पूरे किए

डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

- यह एक अम्बेला कार्यक्रम है, जिसमें कई सरकारी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। इसका समग्र समन्वय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) करता है।
- यह तीन विज्ञान क्षेत्रों की पहचान करता है। (इन्फोफार्मेटिक्स देखें)

डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख उपलब्धियां

- डिजिटल अर्थव्यवस्था: 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया। इसके 2024-25 तक 13.42% तक पहुंचने की उम्मीद है।
 - ⊕ स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर: वर्ष 2014 में 25.15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, जो बढ़कर 2024 में 96.96 करोड़ हो गए। भारतनेट परियोजना के तहत 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है।
- डिजिटल फाइनेंस और वित्तीय समावेशन:
 - ⊕ डिजिटल भुगतान: वर्ष 2023 में वैश्विक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स में भारत की 49% हिस्सेदारी थी। UPI अब 7 से अधिक देशों में लागू है।
 - ⊕ आधार-सक्षम DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): इसने फर्जी लाभार्थियों की पहचान करके लगभग 3.48 लाख करोड़ की बचत की है।
- रणनीतिक तकनीकी क्षमताओं का विकास: इंडियाAI मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (छह परियोजनाएं स्वीकृत) और सेमीकॉन इंडिया 2025 जैसी पहलों से तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिल रही है।
- ई-गवर्नेंस: कर्मयोगी भारत iGOT प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरशाहों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। UMANG/ उमंग ऐप के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं।

प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंडिया	डिजिटल इंडिया के तहत तीन विज्ञान क्षेत्र	गवर्नेंस और मांग पर सेवाएं	नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण
- कोर युटिलिटी के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट - जन्म से मृत्यु तक डिजिटल पहचान - मोबाइल फोन और बैंक खाता - कोजल सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच - पब्लिक क्लराउड पर साझा करने योग्य प्राइवेट स्पेस - सुरक्षित साइबर-स्पेस	- विभागों या अधिकार क्षेत्रों में निबंधन रूप से एकीकृत - ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम में सेवा की उपलब्धता - सभी नागरिक हकदारियों के लिए क्लराउड एक्सेसिबिलिटी - ईन ऑफ इंडिया बिजनेस के लिए डिजिटल रूप से परिवर्तित सेवाएं - इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस वित्तीय लेन-देन - निर्णय समर्थन और विकास के लिए GIS का उपयोग करना	- सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता - सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन - सभी दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों के लिए क्लराउड एक्सेसिबिलिटी - भारतीय भाषाओं में उपलब्ध डिजिटल संसाधन और सेवाएं - सहभागी गवर्नेंस के लिए सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म - क्लराउड के माध्यम से सभी हकदारियों की पोर्टेबिलिटी	

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 'नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF)' प्रगति रिपोर्ट 2025 जारी की

नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) भारत की सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर SDGs की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में भी काम करता है।

रिपोर्ट में उजागर की गई प्रमुख प्रगति:	
जीरो हंगर (SDG-2)	• कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है। प्रति श्रमिक आय 61,247 (2015-16) से बढ़कर 84,100 रुपये (2024-25) हो गई।
स्वच्छ जल और स्वच्छता (SDG-6)	• ग्रामीण क्षेत्रों में सुक्षिप्त पैरजल तक पहुंच 94.57% (2015-16) से बढ़कर 99.62% (2024-25) हो गई।
स्वच्छ ऊर्जा (SDG-7)	• कुल स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 16.02% (2015-16) से बढ़कर 22.13% (2024-25) हुई। • नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 64.04 वॉट प्रति व्यक्ति (2014-15) से बढ़कर 156.31 वॉट प्रति व्यक्ति (2024-25) हो गई।
गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक वृद्धि (SDG-8)	• सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2016 में 22% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया।
उद्योग और नवाचार (SDG-9)	• GDP की उत्पत्ति तीव्रता 2005 से 2020 के बीच 36% कम हुई है। इसका मतलब है कि अब पर्यावरण के अनुकूल यानी हरित विकास हो रहा है।
असमानता कम करना (SDG-10)	• 2011-12 से 2023-24 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू खर्च का गिनी गुणांक 0.283 से घटकर 0.237 हो गया और शहरी क्षेत्रों में यह 0.363 से घटकर 0.284 हो गया।
निम्नोत्पाद उपभोग (SDG-12)	• संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत 2015-16 के 17.97% से बढ़कर 2024-25 में 80.7% हो गया।
भूमि पर जीवन (SDG-15)	• वन आवरण 21.34% (2015) से बढ़कर 21.76% (2023) हो गया।

रिपोर्ट में प्रकट किए गए प्रमुख मुद्दे: किशोरियों में जन्म दर में बढ़ोतरी देखी गई है; सड़क हादसों में मौतों की संख्या बढ़ी है; मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में गिरावट आई है; सरकारी प्राथमिक खर्चों में कमी आई है, यानी जितना खर्च पहले से तय हुआ था, उसकी तुलना में वास्तविक खर्च कम हुआ है आदि।



अन्य सुर्खियां



अंडमान सागर

अंडमान सागर में एक दिन में तीन बार भूकंप आए। ध्यातव्य है कि अंडमान सागर भूकंपीय क्षेत्र V (उच्चतम भूकंप जोखिम क्षेत्र) में आता है।

अंडमान सागर के बारे में

- यह अर्ध-बंद सागर है, जो हिंद महासागर के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है।
- इसके उत्तर में म्यांमार, पूर्व में थाईलैंड और मलेशिया, दक्षिण में इंडोनेशिया और मलक्का जलडमरूमध्य, और पश्चिम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है।
- यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय है। यहाँ अंडमान ट्रेंच स्थित है, जो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने से बना है।
- समुद्री जैव विविधता:
 - ⊕ यह कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे अधिक जैवविविधता वाली समुद्री जगहों में से एक है।
 - ⊕ यह पूर्वी एशियाई-ऑस्ट्रेलियाई फ्लाइंग के साथ प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है।



संथाल विद्रोह

संथाल विद्रोह के 170 साल को हूल (क्रांति) दिवस के रूप में मनाया गया।

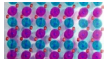
संथाल विद्रोह (1855-56) के बारे में

- यह एक जनजातीय आंदोलन था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था।
 - ⊕ इसे 1857 की क्रांति के लिए प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है।
- यह आंदोलन झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिन-ए-कोह क्षेत्र में हुआ।
- इस आंदोलन का नेतृत्व चार भाइयों- सिदु, कान्हू, चांद-भैरव, और फूलो और झानो मुर्मू ने किया। इन सभी ने मिलकर जमींदारों, पुलिस और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया।
- कारण: इसका कारण 1793 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम था जिसके चलते आदिवासियों को बीरभूम और मानभूम क्षेत्रों (वर्तमान बंगाल) से विस्थापित होना पड़ा और बाद में जमींदारों, पुलिस और अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण किया गया।



सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण

- पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आंतरिक प्रशासनिक पदों पर प्रत्यक्ष नियुक्ति और पदोन्नति के लिए SC (अनुसूचित जाति) और ST (अनुसूचित जनजाति) कर्मचारियों को आरक्षण देने की औपचारिक नीति शुरू की है।
- यह नीति रजिस्ट्रार, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एवं चैम्बर अटेंडेंट आदि सहित कई पदों पर लागू होगी।
 - यह नीति न्यायिक पदों (जजों) पर लागू नहीं होगी।
 - केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुरूप, SC के कर्मचारियों को पदोन्नति में 15% और ST के कर्मचारियों को 7.5% कोटा मिलेगा।



अल्टरमैग्नेट्स (Altermagnets)

- एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (SNBNCBS) के वैज्ञानिकों ने क्रोमियम एंटीमोनाइड (CrSb) का उपयोग करके अल्टरमैग्नेट्स में एक अनोखी विशेषता (duality) की खोज की है।
- परिभाषा: अल्टरमैग्नेट्स एक नए प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, जो फेरोमैग्नेट्स और एंटीफेरोमैग्नेट्स – दोनों की विशेषताओं को मिलाकर बनाता है।
 - फेरोमैग्नेट्स: इसमें इलेक्ट्रॉनों के स्पिन एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, जिससे मजबूत चुंबकत्व पैदा होता है।
 - एंटीफेरोमैग्नेट्स: इसमें इलेक्ट्रॉनों के स्पिन विपरीत दिशाओं में संरेखित होते हैं, जो एक-दूसरे को काट देते हैं। परिणामस्वरूप कोई बाहरी चुंबकत्व नहीं होता है।
 - विशेषताएं:
 - ये एंटीफेरोमैग्नेट्स की तरह ही विपरीत दिशाओं में स्पिन प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनमें कोई चुंबकत्व नहीं होता।
 - लेकिन उनकी अद्वितीय क्रिस्टल समरूपता (crystal symmetry) के कारण, वे फेरोमैग्नेट्स के समान तीव्र आंतरिक स्पिन ध्रुवीकरण दिखाते हैं।
 - CrSb (क्रोमियम एंटीमोनाइड) अब तक के ज्ञात अल्टरमैग्नेट्स में सबसे मजबूत स्पिन-स्प्लिटिंग (spin-splitting) प्रदर्शित करता है।



विलमिंगटन घोषणा

- भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया (QUAD सदस्य) के कोस्ट गार्ड ने विलमिंगटन घोषणा के तहत पहला 'QUAD एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन' लॉन्च किया है।
- यह मिशन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री सहयोग, सुरक्षा और आपसी तालमेल को मजबूत करेगा। साथ ही, यह भारत की समुद्री विज्ञान 'SAGAR (सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास)' को समर्थन देगा।
- विलमिंगटन घोषणा (2024)**
- विलमिंगटन, अमेरिका में क्वाड लीडर्स के द्वारा जारी किया गया।
 - कानून के शासन, लोकतंत्र और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दोहराया गया।
 - शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें:
 - क्वाड कैसर मूनशॉट (फोकस: सर्वाइकल कैसर को खत्म करने पर)
 - मैत्री (MAITRI) - इंडो-पैसिफिक में समुद्री प्रशिक्षण
 - पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप - डिजिटल समुद्री अवसरचना, जैसे कि अंडर-सी केबल का विस्तार करना शामिल है।



वेवएक्स

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MoI&B) ने अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सीलेरेटर कार्यक्रम, वेवएक्स (WaveX) के तहत वेवएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च किया है।
- चैलेंज का शीर्षक: “भाषासेतु- रियल-टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत” है। यह एक राष्ट्रीय हैकाथॉन है। इसका उद्देश्य कम-से-कम 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में AI-संचालित बहुभाषी अनुवाद समाधान विकसित करना है।
 - वेवएक्स के बारे में
 - यह कार्यक्रम MoI&B की WAVES पहल के तहत शुरू किया गया है। वेवएक्स एक स्टार्टअप एक्सीलेरेटर प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य मीडिया, मनोरंजन और भाषा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है।
 - वेवएक्स लक्षित हैकाथॉन, इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के माध्यम से बेहतर विचारों का समर्थन करता है।



महाबोधि मंदिर

- सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें बोधगया मंदिर अधिनियम को चुनौती दी गई थी। यह अधिनियम बिहार के महाबोधि मंदिर परिसर के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। महाबोधि मंदिर परिसर के बारे में
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
 - पहला मंदिर सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था।
 - वर्तमान मंदिर की संरचना 5वीं-6वीं शताब्दी (गुप्त काल के अंत) की है।
 - स्थापत्य संबंधी विशेषताएं:
 - इसमें एक वक्र रेखीय शिखर (curvilinear shikhara) है, जिसके ऊपर आमलक और कलश स्थापित हैं।
 - मंदिर की शैली ना तो पूरी तरह द्रविड़ (दक्षिण भारतीय) है और ना ही नागर (उत्तर भारतीय)।
 - यह नागर शैली की तरह संकीर्ण (narrow) है, लेकिन द्रविड़ शैली की तरह बिना मुड़े सीधे ऊपर उठती है।
 - मुख्य घटक: मुख्य मंदिर, वज्रासन (हीरा सिंहासन), पवित्र बोधि वृक्ष, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़े पवित्र स्थल, मन्त्र स्तूपों और तीन सुरक्षात्मक घेरे (आंतरिक, मध्य, बाहरी)।
 - वैश्विक मान्यता: UNESCO द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।



आपदा चेतावनी प्रणाली

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम (SACHET) को चालू कर दिया है, और इसकी प्रभावशीलता जांचने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट (CB) सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। SACHET (भारत का SMS आधारित चेतावनी प्रणाली) के बारे में
- इसे C-DOT (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स) ने विकसित किया है। यह प्रणाली कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) पर आधारित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने अनुमोदित किया है।
 - यह प्रणाली भारत के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है।
 - चक्रवात, बाढ़, तूफान जैसी आपदा के दौरान यह स्थान-विशेष (Geo-targeted) SMS चेतावनी भेजती है।
 - सेल ब्रॉडकास्ट (CB) के बारे में – लगभग रियल टाइम चेतावनी प्रणाली
 - इसे भी C-DOT द्वारा विकसित किया जा रहा है।
 - CB चेतावनियां सीधे प्रभावित क्षेत्र के सभी मोबाइल फोन पर प्रसारित की जाती हैं।
 - यह SMS की तुलना में बहुत तेज़ है और इसका उपयोग सुनामी, भूकंप, आकाशीय बिजली, गैस रिसाव जैसी अचानक और गंभीर आपदाओं में किया जाता है।

सुर्खियों में रहे स्थल



नामीबिया (राजधानी: विंडहोक)

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा हॉरे के व्यापार पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- नामीबिया में दुनिया के सबसे समृद्ध समुद्री हॉरे के भंडार हैं।
- भौगोलिक अवस्थिति**
- यह अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है।
 - पड़ोसी देश: इसके उत्तर में अंगोला, उत्तर-पूर्व में ज़ाम्बिया, पूर्व में बोत्सवाना, तथा दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका स्थित है।
 - जल निकाय: अटलांटिक महासागर।
- भौगोलिक विशेषताएं**
- नदियां: कुनेने, ओकावांगो, जाम्बेजी, ऑरेंज आदि।
 - मरुस्थल: नामीब, कालाहारी।
 - द ग्रेट एस्कूपमेंट का विस्तार नामीबिया तक है।
 - यहां मौजूद सॉससफ्लेई सैंड झरून्स दुनिया के सबसे ऊँचे रेत के टीलों में से एक हैं।
 - फिश रिवर कैनिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैनिन है।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची